dustries falling within their sphere of activity to pass on the concession and the process is continuing.

(e) The State Weights & Measures Organisations have been asked to intensify their enforcement activities in this regard. At the same time the Administrative Ministries of concerned industries have also been asked to review the position and to take appropriate action against defaulter industries.

(f) and (g) "The maximum retail price. .....inclusive of all taxes" marked on every pre-packed commodity is the maximum limit which a retail dealer may charge from consumer. The actual price of any commodity is left to the free market forces and consumer awareness.

Irregularities at Fair Price Shops

6. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during the recent raids on the fair price shops in the National Capital led by him, it was detected that many FPS were selling essential commodities which were not fit for human consumption apart from other irregularities being comitted by the FPS owners;

(b) if so, what are the details thereof and the action being taken against the FPS owners; and

(c) what action Government propose to take to ensure that only good quality essential items are sold and supplied to the consumers through the Public Distribution System throughout the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) to (c) Minister of the Union Civil Supplies Consumer Affairs and Public Distribution recently visited a number of Fair Price Shops (he did not lead any raids) to assess the functioning of Public Distribution System in the capital. The Food . . Supplies Department of Delhi Administration has powers to carry out enforcement functions. It is reported by Delhi Administration that during the last about 3 months inspections of 10,988 Fair Price Shops have been conducted by officers of the Food & Supplies Department. 62 cases of apparently bad quality of Specified Food Articles were noticed. In 12 such cases, the items were got replaced from F.C.I. through the Delhi State Civil Supplies Corporation. Departmental action has been initiated against 150 PDS outlets for shortcomings. Prosecution has also been launched against 263 PDS outlets for using defective weights & measures.

State Government/UT Administrations are advised, from time to time, to take effective regulatory measure to ensure that good quality stocks of PDS items are made available to consumers through the Fair Price Shops.

उत्तर प्रदेश में राशन की दुकानें

. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में खोली जाने वाली राशन की दुकानों की जिलेवार संख्या कितनी है ;

(ख) ये दुकानें अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों तथा आदिवासी समुदाय के कुल कितने व्यक्तियों के लिए आरक्षित की गई हैं; और

(ग) गत वर्ष 1992-93 के दौरान खोली गई 1141 दुकानों में से कितने प्रतिशत दुकानों का आवंटन उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों को किया गया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कामलुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उचित दर दुकानें

8. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय उचित दर दुकानों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) इन दुकानों का लाभ देश की कुल कितने प्रतिशत आबादी को मिल रहा है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कामलुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) एक विवरण दिया गया है (नीचे देखिए) जिसमें देश में उचित दर की दुकानों का राज्यवार संख्या दी गई है।

सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार देश की समूची आबादी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों की हकदार है। तथापि, यह सम्भव है कि अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे अनेक परिवार हों, जिन्हें राशन कार्ड जारी नहीं किए गए हों अथवा जो अन्यथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन न लेते हों। ऐसे परिवारों की संख्या का ठीक-ठीक आंकलन ज्ञात नहीं है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31-3-93 को उचित दर की दुकानों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	37257
2.	अरुणाचल प्रदेश	509
3.	असम	27034
4.	बिहार	44259
5.	गोवा	577
6.	गुजरात	12874
7.	हरियाणा	6991
8.	हिमाचल प्रदेश	3305
9.	जम्मू व कश्मीर	2633
10.	कर्नाटक	17364
11.	केरल	13050
12.	मध्य प्रदेश	17701
13.	महाराष्ट्र	36643
14.	मणिपुर	1763
15.	मेघालय	3516
16.	मिजोरम	874
17.	नागालैण्ड	473
18.	उड़ीसा	22684
19.	पंजाब	10668
20.	राजस्थान	15617
21.	सिक्किम	1405
22.	तमिलनाडु	21977
23.	त्रिपुरा	1274
24.	उत्तर प्रदेश	74238
25.	पश्चिम बंगाल	20266
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	326
27.	चंडीगढ़	326
28.	दादरा व नगर हवेली	59
29.	दमन व दीव	41
30.	दिल्ली	3555
31.	लक्षद्वीप	31
32.	पांडिचेरी	358
	देश योग :	399738